आईएलआर पंजाब और हरियाणा(1991)2

***समक्ष जेवी गुप्ता सी.जे* और आरएस मोंगिया, जे.**

महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक, - अपीलकर्ता।

बनाम

परवीन कुमार और अन्य-प्रतिवादी।

पत्र पेटेंट अपील संख्या 1990 का 1097.

28 नवंबर, 1990.

*भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम,*1956-रु. 20 और 30—मेडिकल कॉलेज में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए प्रॉस्पेक्टस—ऐसे पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए मेडिकल काउंसिल विनियमन तैयार कर रही है—ऐसे नियमों की प्रकृति—विनियम यदि केवल निर्देशिका है—साक्षात्कार के लिए आवंटित 10 अंक—अंकों को उप-शीर्षों में विभाजित नहीं किया गया है— क्या ऐसा आवंटन अत्यधिक है.

*आयोजित,*योग्यता निर्धारण की प्रक्रिया निर्धारित करते समय प्रॉस्पेक्टस में साक्षात्कार के लिए केवल 10 अंक आवंटित किए गए हैं। जहां तक साक्षात्कार का संबंध है, अंकों को उपशीर्षकों में विभाजित करना आवश्यक नहीं है। साक्षात्कार के लिए आवंटित अंक अत्यधिक नहीं थे।¬¬

(पैरा 9)

*आयोजित,*भारतीय चिकित्सा परिषद का विनियमन कि योग्यता का मूल्यांकन कैसे किया जाना है, केवल निर्देशिका है और अनिवार्य नहीं है और वास्तव में, अधिनियम की धारा 33 के दायरे से बाहर है। यदि चयन प्रतियोगी परीक्षा और योग्यता परीक्षा और साक्षात्कार में प्रदर्शन दोनों के आधार पर हो तो कोई नुकसान नहीं है।¬

*13 जून के आक्षेपित निर्णय के विरुद्ध लेटर्स पेटेंट अपील के खंड एक्स के तहत अपील,*1990 में माननीय श्री न्यायमूर्ति केपी भंडारी द्वारा सिविल रिट याचिका संख्या 1430/1990 में दिया गया।

याचिकाकर्ता की ओर से जेएल गुप्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता, विक्रांत शर्मा, अधिवक्ता और राकेश सिंह, अधिवक्ता।

प्रतिवादियों की ओर से जेके सिब्बल, अधिवक्ता और पवन मुटनेजा, अधिवक्ता।

आदेश

आरएस मोंगिया, जे.

(1) यह निर्णय महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक (इसके बाद इसे विश्वविद्यालय कहा जाएगा) द्वारा दायर लेटर पेटेंट अपील संख्या 1097 और 1098/1990 का निपटान करेगा। 1990 की दो रिट याचिकाएँ संख्या 1430 और 1637, जिनमें से उपर्युक्त दो पत्र पेटेंट अपीलें उत्पन्न हुई हैं, को विद्वान एकल न्यायाधीश के एक सामान्य निर्णय द्वारा अनुमति दी गई थी।

(2) दोनों मामलों के तथ्यों का संक्षिप्त उल्लेख आवश्यक होगा:-

मेडिकल कॉलेज, रोहतक, जो विश्वविद्यालय से संबद्ध है, ने सत्र 1990-91 के लिए कॉलेज में विभिन्न विशिष्टताओं में स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे। स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम तीन वर्ष की अवधि का होता है। जिन छात्रों ने अपना घर का काम नहीं किया है उन्हें तीन साल के डिग्री पाठ्यक्रम के पहले वर्ष में प्रवेश दिया जाना था; जबकि एक साल की घरेलू नौकरी करने वालों को तीन साल के डिग्री कोर्स के दूसरे साल में दाखिला दिया जाना था। पूर्व प्रकार के छात्र जिन्होंने अपना घरेलू काम नहीं किया है यानी नए स्नातक जिन्होंने केवल अपनी इंटर्नशिप पूरी की है, विश्वविद्यालय ने उन्हें समूह II के छात्रों के रूप में वर्णित किया है। 1990 के लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 1097 में उत्तरदाताओं की रिट याचिकाकर्ता समूह II के छात्र हैं। जिन छात्रों ने एक साल का घरेलू काम किया है और तीन साल के डिग्री पाठ्यक्रम के दूसरे वर्ष में प्रवेश पाने के हकदार हैं, उन्हें विश्वविद्यालय द्वारा समूह I के छात्रों के रूप में वर्णित किया गया है। 1990 के लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 1098 में, प्रतिवादी रिट याचिकाकर्ता समूह I के छात्र हैं, समूह I के छात्रों के लिए, 97 सीटें हैं, जिनमें से 24 अखिल भारतीय प्रतियोगी प्रवेश परीक्षा के आधार पर भरी जानी हैं, 20 हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विस (एचसीएमएस) के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं और 53 खुली सीटें हैं जिन्हें लिखित परीक्षा और साक्षात्कार आदि के आधार पर तैयार योग्यता के आधार पर भरा जाएगा, जिसका संदर्भ आगे दिया जाएगा। एचसीएमएस के लिए आरक्षित सीटें केवल लिखित परीक्षा के आधार पर तैयार की गई योग्यता के आधार पर भरी जाती हैं। जहां तक ग्रुप II का सवाल है, कुल 68 सीटें हैं, जिनमें से 16 अखिल भारतीय आधार पर होने वाली परीक्षा के आधार पर भरी जानी हैं, 16 एचसीएमएस के लिए और 36 खुली सीटें हैं। लिखित परीक्षा और साक्षात्कार आदि के आधार पर योग्यता निर्धारित की जाती है।

स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए अधिकारियों द्वारा जारी किए गए प्रॉस्पेक्टस में, योग्यता के निर्धारण की प्रक्रिया के साथ-साथ लिखित परीक्षा के लिए दिशानिर्देश का उल्लेख किया गया है, जो नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है: - "परिशिष्ट ए।

योग्यता निर्धारण की प्रक्रिया... 10 अंक

1. *शैक्षणिक अंक.*- (ए) एमबीबीएस में प्राप्त प्रथम 50 प्रतिशत के लिए 2.5 अंक दिए जाएंगे (सभी का कुल योग)

तीन व्यावसायिक परीक्षाएं) और उसमें 50 प्रतिशत से अधिक प्राप्त कुल प्रतिशत अंकों का 15 प्रतिशत जोड़ा जाएगा। केवल 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को केवल 2.5 अंक दिए जाएंगे और 75 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले दूसरे उम्मीदवार को जी.25 अंक दिए जाएंगे। उसे उपलब्ध कराया :

(बी) ऐसे छात्रों के मामले में जो एक से अधिक प्रयासों में एमबीबीएस परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुए हैं, प्रत्येक अतिरिक्त प्रयास के लिए 1 अंक काटा जाएगा, अधिकतम 5 अंक की कटौती के अधीन।

2. *घर का काम*

10 अंक

प्रत्येक सीनियर और जूनियर हाउसजॉब के लिए पांच अंक होंगे
और हाउसजॉब के दौरान प्रदर्शन को ग्रेड करने की एक प्रणाली होगी। विभिन्न ग्रेड के लिए आवंटित
अंक
इस प्रकार होगा:

ग्रेड ए (उत्कृष्ट उत्कृष्ट)5 अंक।

ग्रेड बी (बहुत अच्छा)3 अंक।

ग्रेड सी (अच्छा)2 अंक।

ग्रेड डी (औसत, संतोषजनक) 1 अंक।

“साक्षात्कार से पहले उस विभाग/इकाई के प्रमुख से साक्षात्कार से पहले उम्मीदवार के प्रदर्शन पर एक रिपोर्ट प्राप्त की जाएगी जहां उसने काम किया है। इस प्रयोजन के लिए छात्रों से उस इकाई के प्रमुख का नाम और नवीनतम पता बताने के लिए कहा जाएगा जिसके साथ उन्होंने गृहकार्य के दौरान काम किया है। दुर्लभ मामलों में यदि संबंधित सलाहकार की अनुपलब्धता के कारण ऐसी रिपोर्ट प्राप्त नहीं की जा सकती है, तो उम्मीदवार को उसकी कुल औसत योग्यता के अनुसार अंक आवंटित किए जाएंगे। प्री-क्लिनिकल विषयों में जहां घरेलू नौकरी आवश्यक नहीं है, अन्य समकक्ष नौकरियों (प्रदर्शक, अनुसंधान अधिकारी आदि) में प्राप्त ग्रेड को समकक्ष माना जा सकता है। इसी प्रकार, जिन अभ्यर्थियों ने घरेलू नौकरी के बदले ग्रामीण/रक्षा सेवा आदि की है, वहां प्राप्त ग्रेड को तदनुसार माना जा सकता है।

महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक बनाम, परवीन कुमार और
अन्य (आरएस मोंगिया, जे.)

3. *प्रशिक्षण।*-3 साल के लिए इंटरशिप के दौरान केवल हाउस-जॉब के स्थान पर सिस्टम प्रदर्शन पर विचार किया जाएगा और तदनुसार अंक आवंटित किए जाएंगे। प्रदर्शन को ग्रेड देने की प्रक्रिया वही होगी जो घरेलू नौकरी के लिए अपनाई जाती है।¬

4. मेडिकल कॉलेज के स्नातकों के लिए वेटेज,
रोहतक. 10 अंक.

5. लिखित परीक्षा : 60 अंक.

6. साक्षात्कार : 10 अंक.

इसमें पेशेवर प्रदर्शन और खेल, अन्य पाठ्येतर गतिविधियों, अन्य सामुदायिक कल्याण कार्यक्रमों में भागीदारी आदि में योगदान को भी ध्यान में रखा जाएगा। साक्षात्कार के समय आवश्यक दस्तावेज जमा किए जाने चाहिए।¬

7. एमडी/एमएस और स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए एचसीएमएस डॉक्टरों का चयन राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय के परामर्श से किया जाएगा।

लिखित परीक्षा के लिए दिशानिर्देश.-इसमें दो पेपर शामिल होंगे:

(A) सभी एमबीबीएस विषयों को कवर करने वाला सामान्य पेपर। 40 अंक.

(B) विषय पेपर (उप से संबंधित प्रश्न)¬
इजेक्ट लागू) 20 अंक।

पेपर ए एमसीक्यू प्रकार का होगा जबकि पेपर बी एमसीक्यू प्रकार या संक्षिप्त नोट्स वाला हो सकता है। पाठ्यक्रम और पाठ्यक्रम तीन पेशेवर एमबीबी9 परीक्षा के समान होंगे, जिसमें विभिन्न विषय शामिल होंगे, एनाटॉमी फिजियोलॉजी, बायोकैमिस्ट्री, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फोरेंसिक मेडिसिन, एसपीएम, जनरल मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, ऑब्स्ट। और स्त्री रोग, नेत्र, ईएनटी और मनोरोग।¬

एमसीक्यू प्रश्नों के लिए नकारात्मक अंकन:

(a) सही उत्तर के लिए पूरा श्रेय दिया जाएगा और ग़लत उत्तर के लिए 1/4 बदनामी दी जाएगी।

(b) एमसीक्यू विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन ऐसे प्रश्न तैयार किए जाएंगे ताकि इसका उत्तर केवल एक अक्षर (ए से ई) के उपयोग से दिया जा सके।

(c) लिखित परीक्षा में 30 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी प्रवेश के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पणी :

1. सामान्य पेपर (ए) में विभिन्न विषयों के अनुमानित अंक एमबीबीएस परीक्षा में इन विषयों को आवंटित अंकों के अनुपात में होंगे।

2. . प्रश्नों का मानक इंटर्न के रूप में प्रशिक्षण सहित एमबीबीएस परीक्षा का होगा। जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं वे अधिकतर व्यावहारिक प्रकृति के होने चाहिए यानी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी जैसे विषयों में। बायो-केमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी आदि, प्रश्न एप्लाइड एनाटॉमी, एप्लाइड फिजियोलॉजी, एप्लाइड बायो-केमिस्ट्री आदि पर होने चाहिए।

3. क्लिनिकल विषयों जैसे मेडिसिन, सर्जरी, स्त्री रोग और प्रसूति विज्ञान आदि में प्रश्न सरल प्रकृति के होने चाहिए, एमबीबीएस मानकों के साथ-साथ इंटर्नशिप/होम उपयोग नौकरी के दौरान प्राप्त प्रशिक्षण अनुभव होना चाहिए।

4. विषय पेपर (बी) में, प्रश्न एमबीबीएस मानक के होंगे। इसके अलावा इंटर्नशिप/घरेलू नौकरी आदि के दौरान सीखे गए कौशल का आकलन करने के लिए पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाएगा।"

उल्लेखनीय है कि प्रॉस्पेक्टस के अनुसार, ग्रुप-I के छात्र भी ग्रुप-II के छात्रों के लिए निर्धारित सीटों के लिए प्रतिस्पर्धा करने के पात्र हैं। हालाँकि ग्रुप 1 और ग्रुप II के लिए एक सामान्य मेरिट सूची होनी है, लेकिन ग्रुप-II के छात्रों की योग्यता देखते समय उनके इंटर्नशिप अंकों को ध्यान में रखा जाना है। समूह-I के छात्र जो समूह-II के छात्रों के लिए निर्धारित सीटों के लिए समूह-II के छात्रों के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, उनके घर की नौकरी के अंकों को उन सीटों के लिए नहीं गिना जाएगा, बल्कि केवल इंटर्नशिप के दौरान प्राप्त उनके अंकों को ध्यान में रखा जाएगा। योग्यता निर्धारण की प्रक्रिया.¬

(3) इसमें आगे उल्लेख किया गया है कि भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 की धारा 3 20 के तहत शक्तियां दी गई हैं

भारतीय चिकित्सा परिषद विश्वविद्यालयों के मार्गदर्शन के लिए और समान मानकों को सुरक्षित करने के मामले में विश्वविद्यालयों को सलाह देने के लिए स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा के न्यूनतम मानक निर्धारित करेगी। इस अधिनियम की धारा 33 मेडिकल काउंसिल को केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी से नियम बनाने की शक्ति देती है। मेडिकल काउंसिल अधिनियम की धारा 20 और 33 नीचे पुन: प्रस्तुत की गई हैं: -

(4) . स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा से संबंधित मामलों में परिषद की सहायता के लिए स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा समिति।—(1) परिषद विश्वविद्यालयों के मार्गदर्शन के लिए स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा के मानक निर्धारित कर सकती है, और वर्दी सुनिश्चित करने के मामले में विश्वविद्यालय को सलाह दे सकती है। पूरे भारत में स्नातकोत्तर शिक्षा के लिए मानक और इस उद्देश्य के लिए केंद्र सरकार परिषद के सदस्यों में से एक स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा समिति (बाद में स्नातकोत्तर समिति के

रूप में संदर्भित) का गठन कर सकती है।

(2) स्नातकोत्तर समिति में नौ सदस्य शामिल होंगे, जिनमें से सभी स्नातकोत्तर चिकित्सा योग्यता और चिकित्सा के स्नातकोत्तर छात्रों को पढ़ाने या उनकी जांच करने का अनुभव रखने वाले व्यक्ति होंगे।¬

(3) स्नातकोत्तर समिति के छह सदस्यों को केंद्र सरकार द्वारा नामित किया जाएगा और शेष तीन सदस्यों को परिषद द्वारा अपने सदस्यों में से चुना जाएगा।¬

(4) किसी विषय में स्नातकोत्तर अध्ययन पर विचार करने के उद्देश्य से, स्नातकोत्तर समिति, जब भी आवश्यक हो, उस विषय में सहायता के लिए योग्य एक या अधिक सदस्यों को शामिल कर सकती है।

(5) सभी मामलों पर स्नातकोत्तर समिति के विचार और सिफारिशें परिषद के समक्ष रखी जाएंगी; और यदि परिषद किसी मामले पर स्नातकोत्तर समिति द्वारा व्यक्त विचारों या की गई सिफारिशों से सहमत नहीं है, तो परिषद उन्हें अपनी टिप्पणियों के साथ निर्णय के लिए केंद्र सरकार को अग्रेषित करेगी,¬¬¬¬

33. *नियम बनाने की शक्ति.—*'दपरिषद, केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी से, इस अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आम तौर पर नियम बना सकती है, और, इस शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित प्रदान कर सकते हैं-¬

(a) परिषद की संपत्ति का प्रबंधन और उसके खातों का रखरखाव और लेखापरीक्षा;

(b) परिषद की बैठकों को बुलाना और आयोजित करना, समय और स्थान जहां ऐसी बैठकें आयोजित की जानी हैं, व्यावसायिक खतरे का संचालन और कोरम का गठन करने के लिए आवश्यक सदस्यों की संख्या;

(c) परिषद के सदस्यों का इस्तीफा;

(d) राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की शक्तियाँ और कर्तव्य;

(e) कार्यकारी समिति और अन्य समितियों की नियुक्ति का तरीका, बैठकें बुलाना और आयोजित करना, और ऐसी समितियों के कामकाज का संचालन;

(f) कार्यालय का कार्यकाल, और रजिस्ट्रार और परिषद के अन्य अधिकारियों और सेवकों की शक्तियां और कर्तव्य;

"(छ) इस अधिनियम के तहत पंजीकरण के लिए आवेदन में बताए जाने वाले विवरण और दी जाने वाली योग्यता का प्रमाण;¬

(h) इस अधिनियम के तहत आवेदनों और अपीलों पर भुगतान की जाने वाली फीस;

(i) चिकित्सा निरीक्षकों और आगंतुकों की नियुक्ति, शक्तियां, कर्तव्य और प्रक्रिया;¬

(j) मान्यता प्राप्त चिकित्सा योग्यता प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालयों या चिकित्सा संस्थानों में पाठ्यक्रम और अध्ययन की अवधि और किए जाने वाले व्यावहारिक प्रशिक्षण, परीक्षा के विषय और उसमें प्राप्त की जाने वाली दक्षता के मानक;¬

(k) कर्मचारियों के मानक; चिकित्सा शिक्षा के लिए उपकरण, आवास, प्रशिक्षण और अन्य सुविधाएं;¬

(l) व्यावसायिक परीक्षाओं का संचालन, परीक्षकों की योग्यता और ऐसी परीक्षाओं में प्रवेश की शर्तें;

(m) चिकित्सकों द्वारा पालन किए जाने वाले पेशेवर आचरण और शिष्टाचार के मानक और आचार संहिता)"¬

ऊपर उल्लिखित शक्तियों के तहत, स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा समिति ने स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के संबंध में कुछ सिफारिशें की थीं और बाद में इन सिफारिशों को मेडिकल काउंसिल अधिनियम की धारा 33 के तहत विनियमों के रूप में अनुमोदित किया गया था। छात्रों के चयन के लिए मानदंड निर्धारित करने और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्र होने के अलावा, यह भी प्रदान किया गया था कि योग्यता का मूल्यांकन कैसे किया जाएगा। अभ्यर्थियों की योग्यता के मूल्यांकन के लिए विनियमों के रूप में निम्नलिखित अनुशंसाएँ निर्धारित की गईं:-¬¬¬¬¬

"योग्यता का मूल्यांकन:-स्नातकोत्तर समिति की राय थी कि स्नातकोत्तर मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए एक उम्मीदवार की योग्यता निर्धारित करने के लिए, (i) एमबीबीएस परीक्षा में उसका प्रदर्शन, (ii) इंटर्नशिप के दौरान उसका प्रदर्शन और हाउसमैनशिप जिसके लिए एक दैनिक मूल्यांकन चार्ट बनाए रखा जाना चाहिए और (iii) समय-समय पर प्रस्तुत की जाने वाली शिक्षकों की रिपोर्ट पर विचार किया जा सकता है।¬¬¬

वैकल्पिक रूप से संबंधित अधिकारी स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए उम्मीदवार की योग्यता निर्धारित करने के लिए प्रतिस्पर्धी प्रवेश परीक्षा आयोजित कर सकते हैं।¬

(4) एकल न्यायाधीश के समक्ष रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए बिंदु यह थे कि साक्षात्कार के लिए 100 में से 30 अंक रखे गए थे, जो बहुत अधिक हैं क्योंकि पक्षपात और भाई-भतीजावाद के लिए जगह थी। इसके अलावा मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की सिफारिशों के अनुसार, साक्षात्कार आयोजित करने का कोई प्रावधान नहीं था और प्रवेश या तो एमबीबीएस परीक्षा में प्रदर्शन और इंटर्नशिप और हाउसमैनशिप के दौरान या वैकल्पिक रूप से एक प्रतिस्पर्धी प्रवेश आयोजित करके होना था।¬

इंतिहान। साक्षात्कार की शुरूआत मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की सिफ़ारिशों के ख़िलाफ़ थी, तीसरा, प्रवेश के विभिन्न स्रोतों के बीच भेदभाव था, क्योंकि जिन छात्रों को अखिल भारतीय परीक्षा के आधार पर प्रवेश दिया जाता है या जो एचसीएमएस हैं, उन्हें बिना किसी साक्षात्कार के प्रवेश दिया जाता है। और इसलिए, जहां तक रिट-याचिकाकर्ताओं का संबंध है, साक्षात्कार की शुरूआत मनमानी और भेदभावपूर्ण थी। विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष यह भी तर्क दिया गया कि चयन समिति का विधिवत गठन नहीं किया गया था।¬¬¬

(5) विद्वान एकल न्यायाधीश ने माना कि साक्षात्कार के लिए 30 प्रतिशत अंक आवंटित किए गए थे, जो बहुत अधिक थे और विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानदंड मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की सिफारिशों का उल्लंघन था, जो अनिवार्य थे और आगे भी। जहां तक साक्षात्कार का प्रश्न है, प्रवेश के विभिन्न स्रोतों के बीच भेदभाव था और चयन समिति का गठन भी ठीक से नहीं किया गया था। इन निष्कर्षों के आधार पर दोनों रिट याचिकाओं को अनुमति दी गई और यह निर्देश दिया गया कि मेरिट सूची केवल दो मामलों को ध्यान में रखते हुए तैयार की जाए यानी लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के अनुसार तैयार की गई मेरिट और महर्षि से एमबीबीएस उत्तीर्ण करने वाले छात्रों के लिए वेटेज। दयानंद विश्वविद्यालय में योग्यता निर्धारण की प्रक्रिया दी गई है। विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले से व्यथित होकर विश्वविद्यालय ने ये दो अपीलें दायर की हैं।¬¬¬¬¬

(6) 20 सितंबर 1990 को इन अपीलों को स्वीकार करते हुए, हमने विद्वान के आक्षेपित निर्णय की कार्रवाई पर रोक लगा दी थी।
एकल न्यायाधीश.

(7) श्री जेएल गुप्ता. अपीलकर्ता के विद्वान वकील वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि विद्वान एकल न्यायाधीश का निर्णय सही था जब उन्होंने कहा कि साक्षात्कार के लिए 100 में से 30 अंक आवंटित किए गए थे। विद्वान वकील के अनुसार साक्षात्कार के लिए केवल 10 अंक आवंटित किए गए थे जो एचएल™ के भीतर थे। एच बीवी सुप्रीम कोर्ट. उन्होंने कहा कि 10 अंक हो गए हैं

केवल 2.5 अंक दिये जायेंगे तथा 75 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले को 6.25 अंक दिये जायेंगे। विद्वान वकील के अनुसार इन अंकों को प्रदान करते समय चयन समिति के पास कोई विवेकाधिकार नहीं था, जैसा कि ऊपर बताया गया है, गणितीय था। इसी प्रकार, वकील ने प्रस्तुत किया कि हाउस-जॉब अंक और इंटर्नशिप अंक उन रिपोर्टों पर निर्भर थे जो छात्रों ने हाउस-जॉब या इंटर्नशिप के लिए काम करते समय प्राप्त किए होंगे, और यहां फिर से, चयन के सदस्यों के साथ कोई विवेकाधिकार नहीं था। जैसा कि योग्यता के निर्धारण की प्रक्रिया में संकेत दिया गया है, समिति फिर से गणितीय थी, जो रिपोर्ट के उत्कृष्ट, बहुत अच्छे, अच्छे या औसत होने पर निर्भर करती थी। विद्वान वकील के अनुसार साक्षात्कार के लिए केवल 10 अंक आवंटित किए गए थे जो इस बात को ध्यान में रखते हुए अत्यधिक नहीं थे कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने के दौरान छात्र का व्यक्तित्व पर्याप्त रूप से विकसित हो और यहां तक कि साक्षात्कार के लिए अंक देते समय भी चयन समिति को यह करना था। पेशेवर प्रदर्शन, खेल में योगदान, अन्य पाठ्येतर गतिविधियों, अन्य सामुदायिक कल्याण कार्यक्रम में भागीदारी आदि को ध्यान में रखें। विद्वान वकील ने अतुल खुल्लर और अन्य बनाम जम्मू-कश्मीर राज्य और अन्य (1) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया। जिसमें साक्षात्कार के लिए 15 प्रतिशत अंकों के आवंटन को बरकरार रखा गया था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निम्नानुसार टिप्पणी की: -¬¬¬¬

> "एक सामान्य दलील थी कि चयन समिति द्वारा लिखित परीक्षा और मौखिक परीक्षा आयोजित करने में अपनाई गई प्रक्रिया अमान्य थी। हमने प्रश्न पत्र तैयार करने और उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में अपनाई गई विस्तृत प्रक्रिया की जांच की है और मामले के अन्य पहलुओं पर विचार किया है। याचिकाकर्ता यह स्थापित करने में सफल नहीं हुए हैं कि प्रक्रिया भौतिक रूप से दोषपूर्ण है। यह आग्रह किया गया है कि कुल 100 अंकों में से मौखिक परीक्षा के लिए केवल 85 अंक आवंटित करने से मौखिक परीक्षा को लिखित परीक्षा से अधिक महत्व मिलता है जो अनुचित है। हम इस बात पर सहमत होने में असमर्थ हैं कि मौखिक परीक्षा के लिए 15 अंकों का आवंटन उम्मीदवार की क्षमता के मूल्यांकन में एक अनुचित असंतुलन पैदा करता है।

(8) श्रीमान श्रीमान £जेकेए] सिब्बल, ■ने उत्तर में छात्रों (रिट-याचिकाकर्ताओं) (अर्थात समूह-II के छात्रों) के लिए उपस्थित होना सीखा।

(1) एआईआर 1986 एससी 1224।

जहां तक उपर्युक्त तर्क का संबंध है, सुप्रीम कोर्ट ने सार्वभौमिक नियम के रूप में यह निर्धारित नहीं किया था कि साक्षात्कार के लिए 15 प्रतिशत अंक आवंटित किए जा सकते हैं और वास्तव में सुप्रीम कोर्ट ने साक्षात्कार के लिए 15 प्रतिशत अंक को बरकरार रखा था क्योंकि ये उप- थे। निम्नलिखित शीर्षकों में विभाजित:-¬

(i) मूल्यांकन5 अंक.

(ii) सामान्य ज्ञान4 अंक।

(iii) सामाजिक गतिविधियाँ3 अंक, और

(iv) व्यक्तित्व परीक्षण3 अंक।

विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि यह कोशल कुमार गुप्ता और अन्य बनाम जम्मू-कश्मीर राज्य के

फैसले से स्पष्ट था। और अन्य (2), जिसका संदर्भ अतुल भुल्लर के मामले (सुप्रा) में दिया गया है। विद्वान वकील ने कहा कि वास्तव में साक्षात्कार के लिए 20 अंक थे, क्योंकि इंटर्नशिप के लिए उम्मीदवारों का कोई रिकॉर्ड नहीं था और प्रशिक्षुओं ने कुछ दिनों से लेकर एक महीने तक विभिन्न व्यक्तियों के अधीन काम किया था और पुरस्कार देने के लिए कोई मानदंड नहीं था। प्रशिक्षुओं को प्रमाणपत्र और यह वास्तव में चयन समिति के विवेक पर छोड़ दिया गया था। इसके अलावा उन्होंने कहा कि साक्षात्कार में अंकों को उप-शीर्षों में विभाजित नहीं किया गया था, जैसा कि कोशल कुमार गुप्ता के मामले में (सुप्रा) था और यहां तक कि साक्षात्कार के लिए जो 10 अंक आवंटित किए गए थे, वे भी बहुत अधिक थे।¬

(9) हम पाते हैं कि अपीलकर्ता की ओर से विद्वान वकील का तर्क बिना किसी योग्यता के है। योग्यता निर्धारण की प्रक्रिया निर्धारित करते हुए प्रॉस्पेक्टस में साक्षात्कार के लिए केवल 10 अंक निर्धारित किये गये हैं। अकादमिक के लिए अन्य 10 अंक और हाउस-जॉब/इंटर्नशिप के लिए 10 अंक सभी गणितीय आधारित अंक हैं और चयन समिति के पास कोई विवेकाधिकार नहीं है जैसा कि ऊपर बताया गया है। इंटर्नशिप के लिए अंक उन विभिन्न व्यक्तियों के मूल्यांकन के आधार पर दिए जाने चाहिए जिनके अधीन प्रशिक्षु ने काम किया होगा। यह अदालत इस तथ्य पर नहीं जा सकती कि प्रशिक्षुओं के लिए कोई रिकॉर्ड रखा जा रहा था या नहीं। हालाँकि, हम विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत रिकॉर्ड से संतुष्ट हैं कि प्रशिक्षुओं के काम के मूल्यांकन के संबंध में कुछ रिकॉर्ड थे। हमारा यह भी मानना है कि ऐसा होना आवश्यक नहीं है¬¬

(2) एआईआर 1984 एससी 1056।

जहां तक साक्षात्कार का संबंध है, अंकों को उप-शीर्षों में विभाजित किया गया है। यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा लीला धर बनाम राजस्थान राज्य और अन्य (3) में आयोजित किया गया था, जिसमें इसे निम्नानुसार देखा गया था: -

> "हमले का दूसरा मैदान भी हमले के पहले मैदान की तरह ही विफल होना चाहिए। नियम स्वयं साक्षात्कार परीक्षा में विभिन्न शीर्षकों के तहत अंकों के आवंटन का प्रावधान नहीं करते हैं। साक्षात्कार परीक्षा के मानदंड नियमावली द्वारा निर्धारित किये गये हैं। यह साक्षात्कार लेने वाली संस्था को सामान्य निर्णय लेना है कि क्या अलग-अलग शीर्षकों के तहत अंक आवंटित किए जाएं या एक ही लॉट में अंक दिए जाएं। विभिन्न मदों के तहत अंक देने से कभी-कभी उम्मीदवार की छवि विकृत हो सकती है। दूसरी ओर, साक्षात्कारकर्ता निकाय पर उम्मीदवार द्वारा बनाई गई धारणा की समग्रता उम्मीदवार के व्यक्तित्व की अधिक सटीक तस्वीर दे सकती है। यह साक्षात्कार लेने वाली संस्था का काम है कि वह प्रत्येक सेवा के लिए चयन के समय अंकन की उचित पद्धति का चयन करे। इन मामलों में कोई जादुई फार्मूला नहीं हो सकता है और अदालतें साक्षात्कार निकायों द्वारा अपनाए गए अंकन के तरीकों पर तब तक फैसला नहीं दे सकतीं, जब तक कि, जैसा कि हमने कहा है। यह सिद्ध या स्पष्ट है कि अंकन का तरीका परोक्ष उद्देश्य से चुना गया था।"¬

ऊपर जो कहा गया है, उसके मद्देनजर, हम मानते हैं कि विद्वान एकल न्यायाधीश का यह मानना सही नहीं था कि साक्षात्कार के लिए 30 प्रतिशत अंक आवंटित किए गए थे, वास्तव में साक्षात्कार के लिए केवल 10 अंक आवंटित किए गए हैं, जो, हमारे विचार से, थे। विशेष रूप से अतुल खुल्लर के मामले (सुप्रा) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ध्यान में रखते हुए अति नहीं।¬

(10) जहां तक प्रश्न 8 का सवाल है कि क्या आपका मानदंड भारतीय चिकित्सा परिषद की सिफारिशों का था, जिन्हें पहले ही ऊपर प्रस्तुत किया जा चुका है, अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील ने

प्रस्तुत किया कि यद्यपि इन सिफारिशों को विनियमों के रूप में अनुमोदित किया गया है, फिर भी ये केवल दिशानिर्देश हैं और अनुशंसात्मक हैं। प्रकृति में और चरित्र में अनिवार्य नहीं हैं। इस प्रस्ताव के लिए, विद्वान वकील ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले, मध्य प्रदेश राज्य और अन्य बनाम कुमारी निवेदिता जैन और अन्य (4) पर भरोसा किया।¬¬¬

(3) एआईआर 1981 एससी 1777।
(4) एआईआर 1981 एससी 2045,

उस मामले में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने यह व्यवस्था दी थी कि मेडिकल कॉलेजों में छात्रों का चयन पूरी तरह से आधार पर होना चाहिए। अभ्यर्थियों की योग्यता एक प्रतियोगी प्रवेश परीक्षा के आधार पर निर्धारित की जा सकती है। सामान्य अभ्यर्थियों को योग्यता परीक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक और प्रवेश परीक्षा में भी 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने के लिए पेक्फ्लिर** एड किया गया था। हालाँकि, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के संबंध में, प्रवेश के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक सामान्य उम्मीदवारों के लिए 50 प्रतिशत के बजाय 40 प्रतिशत होने चाहिए थे। राज्य सरकार ने एक कार्यकारी आदेश द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के संबंध में मेडिकल कॉलेजों में छात्रों के चयन के लिए न्यूनतम योग्यता अंकों से संबंधित शर्तों को पूरी तरह से शिथिल कर दिया है। इस चुनौती को खारिज करते हुए कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए योग्यता में ढील देने वाला राज्य सरकार का कार्यकारी आदेश मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के विनियमन का उल्लंघन है, शीर्ष अदालत ने कहा कि विनियमन केवल निर्देशिका है और अनिवार्य नहीं है। यह भी माना गया कि एक विनियमन जो योग्य उम्मीदवारों में से चयन की प्रक्रिया या प्रक्रिया से संबंधित है, अधिनियम की धारा 33 के तहत मेडिकल काउंसिल के अधिकार से बाहर है, जिसे पहले ही ऊपर दोहराया जा चुका है। उसी सिद्धांत को लागू करते हुए, हम मानते हैं कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का विनियमन कि योग्यता का मूल्यांकन कैसे किया जाना है, केवल निर्देशिका है और अनिवार्य नहीं है और वास्तव में, अधिनियम की धारा 33 के दायरे से बाहर है। यदि चयन प्रतियोगी परीक्षा और योग्यता परीक्षा और साक्षात्कार में प्रदर्शन दोनों के आधार पर हो तो कोई नुकसान नहीं है। वास्तव में, लीला धर के मामले (सुप्रा) में, सुप्रीम कोर्ट ने निम्नानुसार कहा: -¬

"इस प्रकार, लिखित परीक्षा आदमी की बुद्धि का आकलन करती है और साक्षात्कार उचित चयन के लिए आदमी और 'दोनों मिलेंगे' का परीक्षण करता है। यदि लिखित परीक्षा और साक्षात्कार परीक्षा दोनों ही उचित चयन की आवश्यक विशेषताएँ हैं, तो यह प्रश्न उठ सकता है कि उन्हें क्रमशः कितना महत्व दिया जाएगा। उदाहरण के लिए, किसी कॉलेज में प्रवेश के मामले में, जहां उम्मीदवार का व्यक्तित्व अभी विकसित नहीं हुआ है और व्यक्तिगत गुणों की पहचान करना अभी जल्दबाजी होगी, जिसके लिए बाद के जीवन में अधिक महत्व दिया जा सकता है, अधिक महत्व देना अनिवार्य है लिखित परीक्षा में प्रदर्शन के लिए. साक्षात्कार परीक्षा से जुड़ा महत्व न्यूनतम होना चाहिए।¬¬

अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील के इस तर्क को उत्तरदाताओं के विद्वान वकील द्वारा कोई गंभीर चुनौती नहीं दी गई।¬

नतीजतन, हम मानते हैं कि योग्यता के निर्धारण के लिए विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानदंड भारतीय चिकित्सा परिषद की सिफारिशों का उल्लंघन नहीं था।¬

(11) तीसरे बिंदु पर आते हुए कि विभिन्न स्रोतों के बीच भेदभाव था क्योंकि उन उम्मीदवारों के लिए कोई साक्षात्कार नहीं था जिन्हें अखिल भारतीय परीक्षा के आधार पर भर्ती किया गया था या एचसीएमएस से संबंधित उम्मीदवारों के लिए, हमारी राय है कि विद्वान एकल न्यायाधीश नहीं थे सही।

ये पूरी तरह से अलग स्रोत हैं। अखिल भारतीय परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों का साक्षात्कार आयोजित करना आवश्यक नहीं होगा जिसके लिए मानक भिन्न हो सकते हैं। उम्मीदवार देश के दूर-दराज के स्थानों से हैं और प्रत्येक को साक्षात्कार के लिए बुलाना व्यावहारिक नहीं हो सकता है। इसी प्रकार वी ? 3 एचसीएमएस से संबंधित 5 जे उम्मीदवार पहले ही कुछ वर्षों की सेवा कर चुके हैं और अपने सेवा करियर में अनुभव प्राप्त कर चुके हैं। नौकरी पाने के लिए उनका इंटरव्यू हो चुका था. ये सभी अलग-अलग श्रेणियां हैं, इसलिए किसी भेदभाव का सवाल ही नहीं उठता। नतीजतन, हमारा मानना है कि नए लोगों और घर पर नौकरी कर चुके लोगों को साक्षात्कार के अधीन करके योग्यता तैयार करने में कुछ भी गलत नहीं है। यह बात महत्वहीन है कि पीजीआई या अखिल भारतीय चिकित्सा संस्थान जैसे कुछ संस्थानों में कोई साक्षात्कार नहीं होता है। यहां सवाल यह है कि साक्षात्कार देना बुरा है या नहीं, जैसा कि हम पहले ही मान चुके हैं कि यह बुरा नहीं है।¬

(12) विद्वान एकल न्यायाधीश ने माना कि चयन समिति के गठन के संबंध में प्रॉस्पेक्टस में निर्धारित प्रक्रिया बहुत असंतोषजनक है। चयन समिति की अध्यक्षता निदेशक प्राचार्य को करनी है। चयन समिति के अन्य सदस्यों की योग्यता निर्धारित नहीं की गई है। विद्वान न्यायाधीश ने आगे कहा कि चयन समिति की कार्यवाही में भाग लेने के लिए किसी बाहरी विशेषज्ञ को आमंत्रित नहीं किया जाता है। विद्वान एकल न्यायाधीश के संबंध में, हम देख सकते हैं कि रिट याचिका में ऐसी कोई चुनौती नहीं थी। एकमात्र चुनौती यह थी कि गणित विभाग के प्रमुख प्रोफेसर सरबजीत सिंह साक्षात्कार की प्रक्रिया में शामिल थे और किसी भी कल्पना से उन्हें विभिन्न स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के विषयों में विशेषज्ञ नहीं कहा जा सकता था। इस पर विश्वविद्यालय ने जवाब दिया था कि प्रोफेसर सरबजीत सिंह एक वरिष्ठ प्रोफेसर थे और चयन समिति में विश्वविद्यालय के नामांकित व्यक्ति थे, जिसे उम्मीदवारों के समग्र मूल्यांकन का आकलन करना था। चयन समिति में विषयों के विशेषज्ञों को आधार बनाकर शामिल किया गया जिस विषय के लिए साक्षात्कार होना था। परिणामस्वरूप, हमें चयन समिति के गठन में कुछ भी गलत नहीं लगता।

(13) हम समूह- I के छात्रों के लिए विद्वान वकील द्वारा उठाए गए एक बिंदु से निपट सकते हैं कि चयन के मानदंड विश्वविद्यालय के अध्यादेशों का उल्लंघन थे। विद्वान वकील ने विश्वविद्यालय कैलेंडर में होने वाले कुछ अध्यादेशों का हवाला दिया। हमने पाया कि ये अध्यादेश विश्वविद्यालय विभागों में प्रवेश से संबंधित हैं, न कि मेडिकल कॉलेजों जैसे संबद्ध कॉलेजों से। परिणामस्वरूप, हमें समूह-I के छात्रों के लिए विद्वान वकील की प्रस्तुति में कोई योग्यता नहीं मिली।¬

(14) उपरोक्त स्थिति का सामना करते हुए, ग्रुप- II छात्रों के वकील श्री जेके सिब्बल ने कहा कि जिन फ्रेशर्स ने अभी-अभी एमबीबीएस और इंटर्नशिप पूरी की है और जिनके लिए अलग सीटें आरक्षित की गई हैं, उन्हें उन छात्रों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए बनाया गया है जिन्होंने हाउस पूरा कर लिया है। -नौकरी और लिखित परीक्षा यानी पेपर बी के 20 अंकों का पेपर सेट करते समय, वही पाठ्यक्रम/ज्ञान से सेट किया जाता है जो कोई घर-नौकरी करते समय प्राप्त करता है। विद्वान वकील के अनुसार यह उपरोक्त लिखित सूची के दिशानिर्देशों से स्पष्ट था। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने घर पर नौकरी की है, वे निश्चित रूप से पेपर बी में बेहतर प्रदर्शन करेंगे और उन्हें 3 साल के पाठ्यक्रम में प्रवेश मिलेगा और वस्तुतः नए लोगों के लिए कोई आरक्षण नहीं होगा, जिनके लिए वास्तव में 36 सीटें आरक्षित की गई हैं। प्रतियोगिता बहुत कठिन होने के कारण प्रवेश पाने वाले उम्मीदवारों के बीच केवल आंशिक अंतर होगा। विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि वास्तव में दो अलग-अलग परीक्षाएं और मेरिट सूचियां होनी चाहिए, एक समूह I के लिए और दूसरी समूह II के छात्रों के लिए। विद्वान वकील के अनुसार असमानों के बीच प्रतिस्पर्धा थी। उन्होंने अपने तर्क को स्पष्ट करते हुए कहा कि यदि एक नए

महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक बनाम, परवीन कुमार और अन्य (आरएस मोंगिया, जे.)

छात्र को खुली प्रतियोगिता की योग्यता में पहले 53 उम्मीदवारों में रखा जाता है, तब भी उसे समूह I के छात्रों के साथ दूसरे वर्ष में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, हालांकि वह उन लोगों की तुलना में अधिक मेधावी है जिन्होंने घर की नौकरी पूरी कर ली है। . दूसरी ओर, अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील ने कहा कि सर्वोत्तम प्रतिभा प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय हमेशा न्यूनतम से अधिक मानक निर्धारित कर सकता है। प्रारंभिक आपत्तियों के पैरा 6 में विश्वविद्यालय ने अपने लिखित बयान में निम्नानुसार कहा था: -¬¬

> "गृह-नौकरी धारकों को मिलने वाला लाभ सामान्य पेपर के उनके ज्ञान में कमी के कारण रद्द कर दिया जाएगा, जिसमें विशेष पेपर की तुलना में दोगुने अंक थे। इस प्रकार जबकि वे लाभ प्राप्त कर सकते हैं¬

20 अंकों वाले एक क्षेत्र में, उन्हें 40 अंकों वाले क्षेत्र में नुकसान होगा, जिससे तुलनीय या बराबर हो जाएगा।

यह कि जिस उम्मीदवार ने घर पर नौकरी की है, उसने निस्संदेह कुछ बड़ा ज्ञान या कौशल हासिल कर लिया है। हालाँकि यह कौशल उसके 20 अंकों के विशेष पेपर को लेने में थोड़ा योगदान दे सकता है, साथ ही उसे 40 अंकों के सामान्य पेपर के लिए नुकसान होगा जहाँ एक प्रशिक्षु से बेहतर प्रदर्शन करने की अपेक्षा की जाती है क्योंकि उसे पाठ्यक्रमों के बीच समय की कोई हानि नहीं होती है। विभिन्न विषयों में स्नातक की. हाउस सर्जन रहते हुए एक वर्ष की हाउस जॉब के दौरान। तुलनात्मक रूप से एक वर्ष का नुकसान हुआ है।"

(15) हमें विद्वान वकील श्री जेके सिब्बल की दलीलों में दम नजर आता है। नए छात्रों को उन व्यक्तियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए नहीं बनाया जा सकता है जिन्होंने घर का काम किया है, जहां पेपर का कुछ हिस्सा उस पाठ्यक्रम के संबंध में सेट किया गया है जो केवल उन लोगों ने किया है और घर का काम पूरा किया है। यदि इसकी अनुमति दी जाती है तो जिन लोगों ने घर पर काम किया है वे हमेशा नए लोगों पर धावा बोलेंगे। यदि सभी सीटें सभी उम्मीदवारों के लिए खुली होतीं तो स्थिति बिल्कुल अलग होती। चूँकि नए लोगों के लिए विशेष आरक्षण है (इसमें कोई संदेह नहीं है कि जिन लोगों ने घर पर नौकरी की है वे भी नए लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं), उनकी प्रतिस्पर्धा उस पाठ्यक्रम से बाहर होनी चाहिए जिसे नए लोगों ने पूरा किया है, न कि उस पाठ्यक्रम से जो नए लोगों ने कभी नहीं किया है और केवल वे ही व्यक्ति जिन्होंने घर का काम पूरा कर लिया है। यदि इसकी अनुमति दी जाती है तो समूह II के छात्रों के लिए सीटों का आरक्षण भ्रामक हो जाता है। चूंकि वर्तमान मामले में, परीक्षा पहले ही हो चुकी है, इसलिए यह उचित होगा कि जहां तक समूह II के लिए उम्मीदवारों के प्रवेश का सवाल है, लिखित परीक्षा में अंक लेकर मेरिट सूची तैयार की जानी चाहिए। केवल पेपर ए की और इन अंकों के साथ-साथ योग्यता के निर्धारण के मानदंडों में प्रदान किए गए अन्य अंकों की गणना करके योग्यता तैयार की जाएगी। दूसरे शब्दों में कहें तो 80 अंकों में से मेरिट तैयार की जाएगी। वैकल्पिक रूप से पेपर 'ए' में 40 में से अंकों को 60 में से डेढ़ गुना किया जा सकता है और फिर योग्यता के निर्धारण के मानदंडों के अनुसार 100 अंकों में से एक मेरिट सूची तैयार की जा सकती है।¬¬¬

(16) ऊपर दर्ज कारणों से, हम विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले को रद्द करते हैं और मानते हैं: -

(i) कि साक्षात्कार में आवंटित अंक 10 हैं, न कि 30, जैसा कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने माना है और अत्यधिक नहीं हैं;

(ii) कि योग्यता के निर्धारण के लिए निर्धारित मानदंड भारतीय चिकित्सा परिषद की सिफारिशों का उल्लंघन नहीं है;

(हाय) प्रवेश के मानदंड मनमाने ढंग से भेदभावपूर्ण नहीं हैं; और

(iv) चयन समिति का गठन वैध है।

(17) हम आगे मानते हैं और निर्देश देते हैं कि जहां तक ग्रुप II (3 साल का कोर्स) के लिए उम्मीदवारों के प्रवेश का सवाल है, मेरिट सूची या तो 80 अंकों या 100 अंकों में से तैयार की जानी चाहिए जैसा कि ऊपर बताया गया है। परिणामस्वरूप 1990 की एलपीए संख्या 1098 की अनुमति दी गई है जबकि 1990 की एलपीए संख्या 1097 को ऊपर बताई गई सीमा तक आंशिक रूप से अनुमति दी गई है।

(18) निर्णय से अलग होने से पहले, हम यह देख सकते हैं कि विश्वविद्यालय को जितनी जल्दी हो सके प्रवेश को अंतिम रूप देने के लिए कदम उठाना चाहिए और यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास करना चाहिए कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने वाले छात्रों का एक वर्ष बर्बाद न हो। हम पार्टियों को उनकी लागत वहन करने के लिए छोड़ते हैं।¬

एससीके

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

जसप्रीत कौर

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

हिसार, हरियाणा